ग्रीन रिवोल्ट

हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेजः 4

पर्यटन के इकोसिस्टम की ब्रांडिंग के लिए तैयार हो रहा है प्रदेश

रविवारीय, 17 - 23 जनवरी 2021 वर्ष- दो, अंक-24, रांची, कुल पृष्ठ 4 हिन्दी साप्ताहिक R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 www.greenrevolt.news मूल्यः 5 रूपये

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेंट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं ह्वाट्सएप नंबर है।

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

कोरोना से बढे हेल्थकेयर वेस्ट और कोविड वेस्ट

एजेंसियां

सीबीडब्ल्यूटीएफ के जुटाए गए आंकड़ों पर नजर डालने पर पता चलता है कि जनवरी और फरवरी में नियमित बायोमेडिकल वेस्ट पैदा हो रहा था, जबकि मार्च से सितंबर के आंकड़े बताते हैं कि इस दौरान नियमित बायोमेडिकल वेस्ट और कोविड वेस्ट निकला। दिल्ली में बायोमेडिकल वेस्ट में इस अवधि में खास बढ़ोतरी नहीं हुई। यह वेस्ट जनवरी-फरवरी में 800 टन था जो मार्च और अप्रैल में नहीं बढ़ा बल्कि देशव्यापी लॉकडाउन के कारण इसमें कमी आई। मई के बाद यह जनवरी के मुकाबले 5 प्रतिशत बढ़कर 926 टन हो गया। जून और जुलाई में इसमें क्रमशः 11 और 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इस समय देशभर में लॉकडाउन की बंदिशें खत्म हो रही थीं, जबकि संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे थे। जुलाई में बायोमेडिकल वेस्ट और कोविड वेस्ट अपने 1,101.68 टन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। हालांकि अगस्त में इसमें कुछ गिरावट आई लेकिन सितंबर यह फिर बढ़ गया।

वैक्सीन पर इतना संशय क्यों?

वरीय संवाददाता

ऐसा सिर्फ भारत में ही हो सकता है। एक ओर जहां भारतीय वैज्ञानिकों ने कोरोना वैक्सीन के दो स्वदेशी टीके विकसित कर विश्व को कोविड-19 संकट से मुक्ति की राह दिखायी है। वहीं दूसरी ओर एक तबका इन टीकों के कारगर होने से लेकर इसके ट्रायल पर भी शक कर रहा है।

याद किजिये रूस ने स्पुतनिक नाम से सबसे पहले वैक्सीन बनाने का दावा किया और उसे अपने लोगों के लिये उपलब्ध कराना भी शुरू कर दिया, पर उसे लेकर उतना शोर नहीं हुआ जितना भारत में बने एक देशी टीके पर हो रहा है। वर्तमान में भारत की दो कंपनियां कोरोना वैक्सीन बना रही हैं। पहली सीरम इंडिया है जिसने ब्रिटेन के साथ सहयोग कर एक वैक्सीन बनाया है जिस पर किसी ने उंगली नहीं उठाई है, पर ढाई दशक पुरानी कंपनी भारत बायोटेक के कम कीमत के वैक्सीन के कारगर होने पर शोर हो रहा है। मीडिया के एक तबके से लेकर प्रतिर्स्पद्धी तत्वों ने इस पर कई आरोप लगाये हैं। वहीं कुछ डॉक्टरों ने कहा है कि भारत बायोटेक की वैक्सीन को मानक स्तर तक ट्रायल में नहीं रखा गया है और इसके रिजल्ट का पूरी तरह से इंतजार नहीं किया गया है।

कंपनी के निदेशक ने दावा किया है कि हमारी वैक्सीन पानी नहीं है और इसका रिजल्ट सभी लोगों की बोलती बंद कर देगा। इन सबके बीच आरोप लगाने वालों से लेकर आम लोगों को भी यह याद रखना होगा कि एक नयी माहामारी की वैक्सीन जब तक लोगों को लगायी नहीं जायेगी और उसका रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा तब तक यह आरोप प्रत्यारोप बेमानी हैं। पहले भी कई नामी कंपनियों के टीकों के दुष्प्रभाव सामने आ चुके हैं और टीकाकरण के बाद बीमार पड़ना या एक दो दिनों के लिये स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं का होना कोई अप्रत्याशित बात नहीं है। बेहतर हो ये काम चिकित्साविज्ञानियों के ऊपर ही छोड़ दिया जाये।

सारे विश्व की निगाहें भारत की ओर

भारत विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता देश है और विपुल मात्रा में वैक्सीन बनाने के सारे इंतजाम भारत में है। अन्य रोगों के टीकों का उत्पान और सारे विश्व को उपलब्ध कराने में पहले से ही भारत की साख बनी हुयी है। यही कारण है कि सारा विश्व अभी भारत की ओर वैक्सीन के लिये उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। भारत के पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका की तो छोड़िये अमेरिका और यूरोप तक भारत की बाट की जोह रहे हैं। इसका एक कारण पहले से ही वैक्सीन उत्पादन में भारत की मजबूत साख और यूरोप अमेरिका की कंपनियो से बहुत कम कीमत रही है। इन सबके अलावा जो सबसे प्रमुख बात है कि अन्य कंपनियों के टीकों को बहुत ज्यादा रख रखाव और कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता है वहीं भारतीय टीकों को आसानी से मामूली रखरखाव, बर्फ या छोटे शीतलक इंतजामों के साथ भी रखा जा सकता है।

टीका लगने के बाद कितने लोग बीमार हुये?

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, टीका लगने के बाद किसी भी व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि, राजधानी दिल्ली में वैक्सीन लगने के बाद कुछ लोगों में एलर्जी के लक्षण जरूर दर्ज किए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली में 52 लोगों को एलर्जी की शिकायत हुई।एम्स के एक अधिकारी के मुताबिक, इनमें से एक के अंदर गंभीर लक्षण दिखे। फिलहाल उसे अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है।इसके अलावा कोलकाता में वैक्सीन लेने के बाद बीमार पड़ने वाली एक 35 वर्षीय नर्स की स्वास्थ्य स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह पता लगाने के लिए विशेषज्ञों का एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया है कि वह टीका लेने के बाद बेहोश क्यों हो गई। टीकाकरण से जुड़े कुछ अधिकारियों ने बताया कि टीकाकरण अभियान के पहले दिन कुछ तकनीकी समस्याएं भी सामने आईं, लेकिन उन्हें ठीक कर लिया गया।

पहले दिन जिन राज्यों में सबसे ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया, उनमें उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, गुजरात, बिहार और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति के टीकाकरण के बाद मौत की भी सूचना है। मृतक के परिवारवाले टीका लगने के बाद अपने परिजन के मौत की बात कह रहे हैं साथ ही मृतक के पहले से निमोनिया ग्रस्त होने की बात भी कह रहे हैं।

महिलाओं द्वारा संचालित जोहार एग्री मार्ट, किसानों के लिए बन रहा सहायक

- **राज्य के 11 जिलों में हो रहा जोहार एग्री मार्ट का संचालन**
- **चार हजार किसानों को मिला फायदा, करीब 73.4 लाख का कारोबार**

रांची : गिरिडीह के मधुपुर उत्पादक समूह से जुड़ी यशोदा बताती हैं कि पहले हम जैसे किसानों को जानकारी एवं संसाधन के अभाव के कारण ठगी का शिकार बनना पड़ता था। कोई दुकानदार एक्सपायरी बीज दे देता था तो कोई अधिकतम दाम में बिक्री करता था। लेकिन, अब जोहार एग्री मार्ट के जरिए उच्च गुणवत्ता वाले खाद-बीज उचित मूल्य पर उपलब्ध हो रहे हैं। धान की फसल के समय मैंने जोहार एग्री मार्ट के जरिए लगभग 10 प्रतिशत कम कीमत पर खाद-बीज की खरीदारी की थी। धान की फसल अच्छी हुई। हाल के दिनों में मैंने मिर्च का उत्पादन किया। बीज जोहार एग्री मार्ट से खरीदा। गुणवत्तापूर्ण बीज से अत्यधिक उत्पादन हुआ। इससे अच्छा मुनाफा हुआ।

क्या है जोहार एग्री मार्ट?

राज्य में ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत झारखंड स्टेट लाईवलीहुड प्रमोशन सोसाईटी के द्वारा जोहार परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस परियोजना के जरिए ग्रामीण परिवारों को उत्पादक समूह एवं कंपनियों से जोड़कर उन्नत खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन, सिंचाई, लघु वनोपज इत्यादि गतिविधियों के द्वारा उनकी आय में गुणात्मक बढ़ोतरी के कार्य हो रहें हैं, जोहार एग्री मार्ट इसके तहत एक अभिनव पहल है। वर्तमान में जोहार परियोजना अंतर्गत राज्य के कुल 17 जिलों के 68 प्रखंडों में 3900 उत्पादक समूहों का गठन कर करीब 2.10 लाख से ज्यादा परिवारों को जोड़ा गया है, जिससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हुई है।

11 जिलों में हो रहा है संचालन

झारखण्ड के 11 जिलों में संचालित 'एग्री मार्ट' किसानों की पहली पसंद बनती जा रही है। उत्पादक समूह से जुड़े हजारों किसानों के अलावा आम किसानों को भी खाद-बीज एवं अन्य ..... शेष पेज तीन पर

कॉमन कार्प मछली के बीज बिक्री से अच्छी आमदनी प्राप्त करें

कार्प मछलियों में कॉमन कार्प ही एकमात्र मछली है जो स्थिर पानी में भी प्रजनन करती है। अन्य मछलियां बहते पानी के धार में प्रजनन करतीं हैं। परंतु कॉमन कार्प का बीज चिपकने वाला होता है इसलिए यदि किसी तालाब में बड़ी कॉमन कार्प मछलियां है तो माह फरवरी के अंत में तालाब के चारो कोनो पर जलकुंभी के पौधे रख दे। प्रातः काल आप देखेंगे कि वहां मछलियों का हलचल हो रहा है। जब शांत हो जाए तो जलकुंभी के पौधों को निकाल कर उनके जड़ को देखे। यदि जड़ पर सरसों के दाने की तरह अंडे चिपके होंगे तो समझ लीजिए कि आपके तालाब में कॉमन कार्प मछली प्रजनन कर दी है। अब इन अंडो को पौधे सहित एक हापा में रख दें। हापा का एक तिहाई निचला हिस्सा पानी में रहना चाहिए। एक हापा में लगभग एक लाख अंडा रख सकते हैं। तीन चार दिनों में सभी पीले अंडों से बच्चें निकल आएंगे। सफेद अंडे बेकार है। वे खराब हो जाएंगे। इन बच्चों को, जिन्हें स्पॉन कहां जाता है, उन्हें पहले से तैयार नर्सरी तालाब में संचित कर पंद्रह बीस दिनों में बिक्री के लायक बीज तैयार हो जाएंगे।

यदि किसान के पास तालाब में कॉमन कार्प मछली है तो उन्हें जनवरी माह से ही सजग रहना होगा और ध्यान रखेंगे तो आसानी से अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं।

इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए सीधे लेखक से संपर्क कर सकते हैं। Ph. 9430783037

email:coomar2012@gmail.com

फफूंद ,बर्फबारी और नकली दवा से सेब की फसल को नुकसान

एजेंसियां

कश्मीर घाटी के सभी सेब उत्पादक किसान वेंटूरिआ इनएक्वालिस नाम की फंगस से परेशान हैं। कश्मीर के सेबों की फसल इस साल फफूंद का शिकार हो सकती है। लगातार खराब मौसमी परिस्थितियों के चलते ऐसा हुआ है। हालांकि इसके बावजूद सेब खाने योग्य रहेंगे, लेकिन फफूंद के संक्रमण वाली जगह पर निशान रह जायेगा, जिसकी वजह से किसानों को उसका अच्छा दाम मिलना आसान नहीं होगा। घाटी के सभी सेब उत्पादक किसान वेंटूरिआ इनएक्वालिस नाम की फंगस से परेशान हैं।

एक सेब किसान का कहना है कि "फंगल इन्फेक्शन होना असामान्य बात नहीं है, लेकिन मैंने अपने 35 साल के व्यापार के दौरान इसकी इतनी व्यापकता और गंभीरता नहीं देखी। उन्होंने बताया कि उनकी फसल इस साल सिर्फ 30 पेटी हुई है, जबकि 150 से 250 पेटी फसल आमतौर पर होती है।

रांची रेल मंडल में खेल गतिविधियां पुनः प्रारंभ

रांची : कोरोनावायरस के संक्रमण से बचाव के लिए मार्च 2020 से रांची रेल मंडल पर खेल संबंधी सभी गतिविधि को स्थगित किया गया था।

17 जनवरी को हटिया स्थित एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में मुख्य अतिथि पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी सैयद सबा करीम ने प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन कर पुनः खेल गतिविधियों को प्रारंभ किया तथा खिलाड़ियों के बीच ट्रैक सूट का वितरण किया गया। इस अवसर पर सैयद सबा करीम ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया तथा अपनी फिटनेस पर ध्यान देने को कहा।खेल प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन तथा रांची रेल मंडल पर पुनः खेल गतिविधियों के प्रारंभ के अवसर पर रांची रेल मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक (परिचालन) एम एम पंडित, अपर मंडल रेल प्रबंधक (इंफ्रा) सतीश कुमार ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी ।

इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल अभियंता अमित कंचन, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सह मंडल क्रीड़ा अधिकारी अवनीश, वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता ए आर दास, वरिष्ठ मंडल सिग्नल एवं दूरसंचार अभियंता श्री एस उरांव, मंडल सुरक्षा आयुक्त श्री प्रशांत यादव, मंडल वित्त प्रबंधक टीकाराम मीणा, मंडल वाणिज्य प्रबंधक सह संयुक्त क्रीड़ा अधिकारी डॉ देवराज बनर्जी, खेल सचिव श्री प्रशांत मुखर्जी तथा राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान श्रीमती सुमराय टेटे, पूर्व राष्ट्रीय फुटबॉल रेफरी श्री ओम प्रकाश ठाकुर एवं कर्मचारी तथा खिलाड़ी उपस्थित थे।

हमारे खान-पान की प्रकृति और मधुमक्खी की भूमिका

सुनीता नारायण

जब से हमने शहद में मिलावट का खुलासा किया है, हमें एकदम किताबी किस्म की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। ये वही प्रतिक्रियाएं हैं जो दुनिया भर के बिजनेस स्कूल में सिखाई और पढ़ाई जाती हैं। सबसे पहला कदम आरोपों को नकारने का होता है। इस मामले में शहद बेचने वाली कंपनियां यह रोना रो रही हैं कि हमने चीजों को गलत समझा है। दूसरा कदम है हम पर इल्जाम लगाना और यह आशा करना कि कोई इल्जाम टिक जाएगा। इसके बाद वे वैज्ञानिक शब्दों की जुगाली कर उपभोक्ताओं को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। इस मामले में कंपनियां तमाम जांच रिपोर्ट पेश कर रही हैं और कह रही हैं कि हमारी जांच गलत थी। तीसरा कदम है एक वैकल्पिक विचार तैयार करना जिसमें कहा जाता है कि उनका उत्पाद सही और सुरक्षित है। इस प्रक्रिया में भी वे विज्ञान का सहारा लेकर शाब्दिक हेरफेर करते हैं। याद रहे कि जब सेंटर फॉर साइंस ऐंड एन्वायरनमेंट (सीएसई) ने कोला (शीतल पेयों) में कीटनाशक होने की जांच की थी तब दो बड़ी कंपनियों ने बॉलीवुड के शीर्ष अभिनेताओं को प्रयोगशाला में पहने जाने वाले कोट पहनाकर प्रचार में उतारा और जनता को यह यकीन दिलाया कि सब ठीक है। इस बार भी सफेद कोट वाले लोग उपभोक्ताओं को बता रहे हैं कि इन कंपनियों के उत्पाद सुरक्षित हैं क्योंकि उनकी शुद्धता की जांच की गई है। वे यह नहीं बताते कि जांच में समस्या है।

हमारा अध्ययन बताता है कि चीनी कंपनियों और अब भारतीय कंपनियों ने भी ऐसे सिरप तैयार कर लिए हैं जो शहद की शुद्धता की जांच में खरे उतरते हैं। उन्हें लगता है कि इतना पैसा खर्च करके वे हमारी आवाज को दबा देंगे। उनके आक्रमण की चौथी कतार अधिक सूक्ष्म है और इसकी शुरुआत कोला के खिलाफ जंग के समय हुई थी। अब कंपनियां सीधे हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं करातीं। वे हमें भयभीत करती हैं लेकिन अदालत में नहीं जातीं। इसके बजाय वे ताकत का इस्तेमाल करके हम पर हमले की तैयारी करती हैं।अतीत में यह काम नहीं आया और हमारा मानना है कि इस बार भी यह काम नहीं आएगा। कोला के मामले में हमारी जांच के लिए नियुक्त संयुक्त संसदीय समिति ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया। हम मानते हैं कि इस बार भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण समेत सरकार को हमारी रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ भोजन की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। उसे मिलावट रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। हम सभी जानते हैं कि फिलहाल काफी कुछ दांव पर लगा है। परंतु इसकी एक और वजह हैं मधुमक्खियां। वे हमारी खाद्य प्रणाली की बेहतरी के बारे में इंगित करती हैं। बिना उनके कोई खाद्य पदार्थ नहीं होगा।

शहद क्यों? मधुमक्खी क्यों? क्योंकि प्रकृति की यह सेना हमारी खाद्य प्रणाली की उत्पादकता के लिए अहम है। इनके द्वारा बनाया जाने वाला शहद हमारी बेहतरी और सेहत के काम आता है। इतना तो हम जानते हैं। लेकिन हम इस बात की अनदेखी कर देते हैं कि हम प्रकृति का यह उपहार बहुत जल्दी गंवा सकते हैं।

मधुमक्खियां उत्पादकता के लिए बहुत अहम हैं क्योंकि वे पौधों से परागण करती हैं। व्यापक तौर पर देखें तो फूलों वाले पौधों में से 90 प्रतिशत को परागण के प्रसार के लिए उनकी आवश्यकता होती है। हम जिन फसलों का सेवन करते हैं, उन्हें भी मधुमक्खियों की आवश्यकता होती है। सरसों जैसी तिलहन फसलों से लेकर सेब, खट्टे फलों और फलियों तक मधुमक्खियां काम आती हैं। वे हमेशा से हमें कीटनाशकों की विषाक्तता और उनके अत्यधिक उपयोग को लेकर चेताती रही हैं। मधुमक्खियों को सबसे अधिक नुकसान नियोनिकोटिनॉइड कीटनाशकों ने पहुंचाया। इस श्रेणी के कीटनाशक कीटों की तंत्रिका कोशिकाओं पर हमला करते हैं। इस वर्ष मई में अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ने 12 ऐसे कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगा दिया ताकि परागण हो सके। परंतु अन्य तरह के कीटनाशकों का प्रयोग जारी है और मधुमक्खियां हमें बताती हैं कि कैसे हम अपने भोजन और पर्यावरण को विषाक्त बना रहे हैं।

कच्चे शहद की कीमतों में गिरावट आई और यह तब हुआ जब कि शहद की खपत में कई गुना इजाफा हो चुका था। मधुमक्खीपालन करने वालों का कारोबार ठप हो रहा है। हमें इससे चिंतित होना चाहिए क्योंकि उनकी आजीविका हमारे भोजन से जुड़ी है। बात केवल इतनी ही नहीं है। सच यह है कि औद्योगिक स्तर पर किए जाने वाले आधुनिक मधुमक्खीपालन की भी चर्चा की जानी चाहिए। मधुमक्खियों की जैव विविधता का भी मसला है। यूरोपीय संघ को दुनिया भर में जैवविविधता संरक्षण का अगुआ माना जाता है। वह अपने शहद के बारे में कहता है कि दुनिया के किसी अन्य क्षेत्र की मधुमक्खी उसके जैसा शहद नहीं बनाती। प्रश्न यह है कि इसका मधुमक्खियों की जैव विविधता पर क्या प्रभाव होता है? भारत में भारतीय मधुमक्खी या पहाड़ी मधुमक्खियां होती हैं। यदि इनसे शहद नहीं मिलेगा, यदि इन प्रजातियों को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा?

शहद का प्रसंस्करण किया जाता है। इसे गर्म किया जाता है और निर्वात में सुखाया जाता है ताकि इसमें से रोगाणु समाप्त किए जाएं और इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। परंतु क्या ये मानक उस शहद पर कारगर हैं जिसे शुद्ध शहद कहा जाता है। यानी जिसे मधुमक्खियां तैयार करती हैं और हम जिसे शुद्धतम रूप में ग्रहण करते हैं। तब यह बड़ा उद्योग कैसे बचेगा? बुनियादी सवाल केवल शहद में मिलावट का नहीं बल्कि उससे कहीं बढ़कर है। यह सवाल भविष्य के भोजन की प्रकृति से भी जुड़ा है।

कोरोना वैक्सीन के बाद नॉर्वे में 23 लोगों की मौत, सरकार ने दिया स्पष्टीकरण

नॉर्वे की मेडिसिन एजेंसी ने कहा कि मरने वाले बुजुर्ग थे और कई गंभीर बीमारियों से ग्रस्त थे

एजेंसियां :नॉर्वे में नॉवेल कोरोनावायरस (कोविड-19) की वैक्सीन के चलते 23 मौतें दर्ज हुई हैं। नॉर्वे की दवा एजेंसी स्टैटेंस लेगेमिडेलवर्क ने 14 जनवरी को बताया कि इनमें से 13 मौतों का आकलन किया गया है।

एजेंसी ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि, "वैक्सीन लगवाने के बाद की सभी मौतों की सावधानीपूर्वक जांच की जा रही है। 27 दिसंबर, 2020 को टीकाकरण शुरू होने के बाद अब तक 25,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। संबंधित मामलों में फाइजर कंपनी की एमआरएनए आधारित वैक्सीन इस्तेमाल की गई थीं। राज्य-संचालित ब्रॉडकास्टर एनआरके ने 14 जनवरी को रिपोर्ट में बताया कि एजेंसी ने वैक्सीन के दुष्प्रभावों की जांच की है और 29 रिपोर्ट तैयार की हैं।

ग्रीन रिवोल्ट
हरित-नीरा रहे वसुंधरा

खतरे में है अंधकार

अब तक हम मनुष्यों ने अंधकार को सदैव एक खलनायक के रूप में ही देखा है। हम तो कहते भी आये हैं कि तमसो मा ज्योर्तिगमय। लेकिन अंधकार की भी अपनी एक महत्ता है। जीवन के लिये अंधकार भी आवश्यक है। अगर हम वैज्ञानिक नजरिये से अपनी पृथ्वी को देखें तो ऐसा लगता है कि किसी सर्वशक्तिमान ने सब कुछ हमारे अनुकूल गढा है। चौबीस घंटे में घंटे दिन ताकि हम काम कर सकें। उसके बाद रात ताकि इस पृथ्वी के सारे जीव उस अंधकार की गोद में आराम कर सकें। विश्राम से फिर से ऊर्जा एकत्र कर सकें। यानि बिना अंधकार के जीवन चक्र भी रूक जायेगा। लेकिन हमने क्या किया। अंधकार को रोशनी से परास्त करने के चक्कर में अब ऊर्जा प्राप्त करने की बेतहाशा होड़ और प्रदूषण के एक नये प्रकार को पैदा किया है। जो ***प्रकाश प्रदूषण*** है।

प्रकाश प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। यह न केवल अनावश्यक ऊर्जा और धन की क्षति है, बल्कि इसके और भी कई दुष्परिणाम हैं। हर जगह प्रकाश अक्सर हमारे समकालीन जीवन में शामिल बिन बुलाए मेहमान की तरह है। यह उन कृत्रिम उपकरणों से निकलता है, जिसका हम इस वातावरण में उपयोग करते हैं। इस बीच, अंधेरा अवांछित प्रतीत होता है। आखिर हम यह कैसे मानने लगे कि अगर शहर प्रकाश से चकाचौंध नहीं है तो यह परेशान करने वाली बात है और यहां तक कि हमारे लिए खतरा भी है ?प्रगतिशील पश्चिमी व्यक्ति हमेशा अपने बेहतर की कोशिश में रहता है। मोमबत्ती से लेकर तेल का दीपक, तेल का दीपक से लेकर गैसलाइट तक, गैसलाइट से लेकर बिजली की रोशनी तक, तेज रोशनी की उसकी तलाश कभी बंद नहीं होती। वह अंधेरा की छाया को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। हम भारतीय भी पश्चिम के उसी रस्ते पर चल रहे हैं। आखिर अंधेरे को जगमग रोशनी से मिटा कर हम स्वयं के जीवन चक्र को भी नष्ट कर रहे हैं।

यह कोई छोटी बात नहीं है। वैज्ञानिक इसे वैश्विक चुनौती के रूप में देख रहे हैं। इंटरनेशनल डार्क-स्काई एसोसिएशन ने बताया है कि इससे ऊर्जा और धन दोनों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अकेले अमेरिका में यह नुकसान 3.3 अरब डॉलर तक बढ़ चुका है और प्रत्येक वर्ष 2.1 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड का अनावश्यक उत्सर्जन होता है। चिंता की बात यह है कि इसका मानव स्वास्थ्य, अन्य प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्र पर विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा हैं।

रात में कृत्रिम प्रकाश के संपर्क में आने से मनुष्यों की सर्केडियन लय (शरीर की अंतरिक घड़ी) बाधित हो जाती है। इससे लंबे समय तक या शिफ्ट में काम करने वालों में कैंसर, ह्रदय रोग, मधुमेह, मोटापा और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल विकारों जैसे रोगों का खतरा होता है। ब्रिटेन में अब नौ कर्मचारियों में से एक रात्रि श्रमिक हैं। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

दिल्ली में 2,384 टन कोविड कचड़ा पैदा हुआ

दिल्ली में कोरोनावायरस महामारी शुरू होने के बाद से कुल 2,384 टन ''कोविड-19 वेस्ट'' स्वास्थ्य केंद्रों, क्वारंटाइन सेंटर और होम आइसोलेशन से निकला है। गैर लाभकारी संगठन टॉक्सिक लिंक की रिपोर्ट ''कोविड वेस्टः हाउ दिल्ली मैनेज्ड इट'' के अनुसार, मार्च 2020 के बाद संक्रमण के मामले बढ़ने के साथ कोविड-19 वेस्ट पैदा होना शुरू हुआ। मार्च में संक्रमण के कुल 440 मामले थे, जो अप्रैल में बढ़कर 3,515 हो गए। इसी के साथ कोविड-19 वेस्ट भी मार्च में 33 टन से बढ़कर अप्रैल में 238 टन हो गया। यानी कि कोविड वेस्ट में 620 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

संक्रमण के मामले बढ़ने के अलावा इसमें बढ़ोतरी का बड़ा कारण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की गाइडलाइन थीं, जिसमें कहा गया था कि कोविड-19 मरीजों से पैदा हुआ बायोमेडिकल वेस्ट अलग करके जलाया जाएगा। इससे रिसाइकल होने वाला वेस्ट, डिस्पोजेबल प्लास्टिक और खाद्य सामग्री आदि भी कोविड वेस्ट में शामिल हो गई। रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई में कोविड-19 वेस्ट 511 टन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। ऐसा मुख्य रूप से इस वजह से हुआ, क्योंकि जुलाई तक कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी (सीबीडब्ल्यूटीएफ) तक सामान्य कचरे में मिलकर कोविड वेस्ट आ रहा था।

रिपोर्ट बताती है कि इतनी बड़ी मात्रा में कचरे को जलाना चिंता का सबब था। ऐसा इसलिए भी क्योंकि दिल्ली के सीबीडब्ल्यूटीएफ में कचरे को निर्धारित मात्रा में ही जलाया जा सकता है। जलाने वाले कचरे की मात्रा में इजाफा होने से इनमें दबाब बढ़ गया। इस मिश्रित कचरे को जलाने से डाइऑक्सिन और फ्यूरंस निकलता है जिससे कैंसर का खतरा रहता है। टॉक्सिक लिंक के अनुसार, दिल्ली में सरकार ने हलके लक्षणों वाले मरीजों के लिए होम क्वारंटाइन को प्राथमिकता दी थी। ऐसे घरों से निकला बायोमेडिकल कचरा सामान्य घरेलू कचरे में मिल गया और इस तरह कोविड-19 वेस्ट में बहुत इजाफा हुआ।

दमघोटू प्रदूषण की चादर में लिपटी दिल्ली

ललित गर्ग

कहते हैं जान है तो जहान है, लेकिन दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण जान और जहान दोनों ही खतरे में हैं। दिल्ली की हवा में घुलते प्रदूषण का 'जहर' लगातार खतरनाक स्थिति में बना होना चिन्ता का बड़ा कारण हैं। प्रदूषण की अनेक बंदिशों एवं हिदायतों के बावजूद प्रदूषण नियंत्रण की बात खोखली साबित हुई। यह कैसी शासन-व्यवस्था है? यह कैसा अदालतों की अवमानना का मामला है? यह सभ्यता की निचली सीढ़ी है, जहां तनाव-ठहराव की स्थितियों के बीच हर व्यक्ति, शासन-प्रशासन प्रदूषण नियंत्रण के अपने दायित्वों से दूर होता जा रहा है। यह कैसा समाज है जहां व्यक्ति के लिए पर्यावरण, अपना स्वास्थ्य या दूसरों की सुविधा-असुविधा का कोई अर्थ नहीं है। जीवन-शैली ऐसी बन गयी है कि आदमी जीने के लिये सब कुछ करने लगा पर खुद जीने का अर्थ ही भूल गया, यही कारण है दिल्ली की जिन्दगी विषमताओं और विसंगतियों से घिरी होकर कहीं से रोशनी की उम्मीद दिखाई नहीं देती। क्यों आदमी मृत्यु से नहीं डर रहा है? क्यों भयभीत नहीं है? दिल्ली की जनता दुख, दर्द और संवेदनहीनता के जटिल दौर से रूबरू है, प्रदूषण जैसी समस्याएं नये-नये मुखौटे ओढ़कर डराती है, भयभीत करती है। मालूम हो कि स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी के मुताबिक भारत के तीन बड़े शहर, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई, दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल हैं। जो कि एक चिंताजनक बात है। दिल्ली में प्रदूषण जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गयी है। हर कुछ समय बाद अलग-अलग वजहों से हवा की गुणवत्ता का स्तर 'बेहद खराब' की श्रेणी में दर्ज किया जाता है और सरकार की ओर से इस स्थिति में सुधार के लिए कई तरह के उपाय करने की घोषणा की जाती है। हो सकता है कि ऐसा होता भी हो, लेकिन सच यह है कि फिर कुछ समय बाद प्रदूषण का स्तर गहराने के साथ यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर इसकी असली जड़ क्या है और क्या सरकार की कोशिशें सही दिशा में हो पा रही है। इस विकट समस्या से मुक्ति के लिये ठोस कदम उठाने होंगे। दिल्ली के सामाजिक संरचना में बहुत कुछ बदला है, मूल्य, विचार, जीवन-शैली, वास्तुशिल्प, पर्यावरण सब में परिवर्तन है। आदमी ने जमीं को इतनी ऊंची दीवारों से घेर कर तंगदील बना दिया कि धूप और प्रकाश तो क्या, जीवन-हवा को भी भीतर आने के लिये रास्ते ढूंढ़ने पड़ते हैं। सुविधावाद हावी है तो कृत्रिम साधन नियति बन गये हैं। चारों तरफ भय एवं डर का माहौल है। यह भय केवल प्रदूषण से ही नहीं, भ्रष्टाचारियों से, अपराध को मंडित करने वालों से, सत्ता का दुरुपयोग करने वालों से एवं अपने दायित्व एवं जिम्मेदारी से मुंह फैरने वाले अधिकारियों से भी है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम अब भी ऐसे मुकाम पर हैं, जहां सड़क पर बाएं चलने या सार्वजनिक जगहों पर न थूकने जैसे कर्तव्यों की याद दिलाने के लिए भी पुलिस की जरूरत पड़ती है। जो पुलिस अपने चरित्र पर अनेक दाग ओढ़े हैं, भला कैसे अपने दायित्वों का ईमानदारी एवं जिम्मेदारी से निर्वाह करेंगी? इनदिनों दिल्ली में तेज हवा की वजह से पारा में तेज गिरावट तो आई और उससे ठंड की तस्वीर और बिगड़ी, मगर उससे हवा के साफ होने की भी गुंजाइश बनी थी। अब एक बार फिर दिल्ली में कोहरे या धुंध की हालत बनने के साथ वायुमंडल के घनीभूत होने की हालात पैदा हो गई है और इसमें प्रदूषण की मात्रा बढ़ गई है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत वायु गुणवत्ता और मौसम पर नजर रखने वाली संस्था 'सफर' ने जो ताजा आकलन जारी किया है, उसके मुताबिक दिल्ली में एक बार फिर प्रदूषण की स्थिति गंभीर होने वाली है। दरअसल, वायु की गुणवत्ता की कसौटी पर दिल्ली पहले भी अक्सर ही चिंताजनक हालत में रही है। ऐसे बहुत कम मौके आए, जब इसमें राहत महसूस की गई। पिछले साल पूर्णबंदी लागू होने के बाद जब वाहनों और औद्योगिक इकाइयों का संचालन नाममात्र का रह गया था, तब न सिर्फ वायु, बल्कि यमुना में भी प्रदूषण की समस्या में काफी सुधार देखा गया था। लेकिन उसके बाद पूर्णबंदी में क्रमशः ढिलाई के साथ-साथ जब आम जनजीवन सामान्य होने लगा है, तब धुएं और धूल के हवा में घुलने के साथ ही प्रदूषण ने फिर से अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है।

'सफर' के ताजा आकलन के मुताबिक दिल्ली में वायु गुणवत्ता का स्तर चार सौ इकतीस अंकों तक पहुंच गया। गौरतलब है कि वायु गुणवत्ता का यह स्तर 'गंभीर श्रेणी' में माना जाता है और यह आम लोगों में सांस से संबंधित कई तरह की दिक्कतों के लिहाज से जोखिम की स्थिति है। ज्यादा चिंताजनक यह है कि इसमें अगले कुछ दिनों तक और गिरावट आने की आशंका जताई गई है। 'सफर' के अनुसार वायु गुणवत्ता का स्तर चार सौ उनसठ अंक तक पहुंच सकता है। सारे कानून-कायदों, अदालती या सरकारी आदेशों और पुलिस की कवायद के बावजूद प्रदूषण दिल्ली में कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा। वैसे भी, भारत दुनिया के चुनिंदा देशों में है, जहां शायद सबसे अधिक कानून होंगे, लेकिन हम कितना कानून-पालन करने वाले समाज हैं, यह किसी से छिपा नहीं है।

यों इस मौसम में दिन की शुरूआत यानी सुबह के समय कोहरे या धुंध की चादर का घना होना कोई हैरानी की बात नहीं है। यह कड़ाके की ठंड के दिनों की एक खासियत भी है और विवशता भी। लेकिन मुश्किल यह है कि वायुमंडल के घनीभूत होने की वजह से जमीन से उठने वाली धूल और वाहनों से निकलने वाले धुएं के छंटने की गुंजाइश नहीं बन पाती है। नतीजन, वायु में सूक्ष्म जहरीले तत्व घुलने लगते हैं और प्रदूषण के गहराने की दृष्टि से इसे खतरनाक माना जाता है। हमारा राष्ट्र एवं राजधानी नैतिक, आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक एवं व्यक्तिगत सभी क्षेत्रों में मनोबल के दिवालिएपन के कगार पर खड़ी है। और हमारा नेतृत्व गौरवशाली परम्परा, विकास और हर प्रदूषण खतरों से मुकाबला करने के लिए तैयार है, का नारा देकर अपनी नेकनीयत का बखान करते रहते हैं। पर उनकी नेकनीयती की वास्तविकता किसी से भी छिपी नहीं है, देश की राजधानी और उसके आसपास जिस तरह प्रदूषण नियंत्रण की छीछालेदर होती रहती है, उससे यह सहज ही जाहिर हो गया है। बात सरकार की अक्षमता की नहीं है। उन कारणों की शिनाख्त करने की है, जिनके चलते एक आम नागरिक पर्यावरण या उसके अपने स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर मंडरा रहे खतरों के बावजूद लगातार उदासीन एवं लापरवाह क्यों होता जा रहा है।

दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के मसले पर केंद्र और राज्य सरकारें लगातार बैठकें करती रही हैं, लेकिन प्रदूषण के स्तर में कोई खास कमी नहीं आई है। इस मुद्दे पर राजनीति भी खूब देखने को मिली। इस बीच लांसेट प्लैनेटरी हेल्थ पत्रिका की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक वायु प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर दिल्ली पर ही पड़ा है। इसके बाद नंबर आता है हरियाणा का। प्रदूषण के चलते साल 2019 में दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय में करीब 4,578 रुपये की गिरावट दर्ज की गई। वहीं, हरियाणा को प्रति व्यक्ति आय के रूप में करीब 3,973 रुपये का नुकसान हुआ। ऐसे में प्रदूषण की रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाए जाने कि जरूरत बताई गई, जिसके बाद आज सीपीसीबी ने दिल्ली-एनसीआर में हॉट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर पर 2 जनवरी 2021 तक के लिए बैन लगा दिया है। हालांकि, इससे कितना प्रदूषण कम होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।

फिलहाल दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर होने की वजह साफ दिख रही है। विडंबना यह है कि जब भी प्रदूषण की समस्या खतरनाक हालत में पहुंचती है, तब सरकारें कुछ प्रतीकात्मक उपाय करके सब कुछ ठीक हो गया मान लेती है, लेकिन इस जटिल एवं जानलेवा समस्या का कोई ठोस उपाय सामने नहीं आता। मसलन, कुछ समय पहले दिल्ली में सरकार की ओर से प्रदूषण की समस्या पर काबू करने के मकसद से चैराहों पर लगी लालबत्ती पर वाहनों को बंद करने का अभियान चलाया गया था। सवाल है कि ऐसे प्रतीकात्मक उपायों से प्रदूषण की समस्या का कोई दीर्घकालिक और ठोस हल निकाला जा सकेगा।

उष्णकटिबंधीय जंगलों में मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं बड़े स्तनधारी

एजेंसियां

अध्ययन से पता चला है कि इन फल खाने वाले जानवरों के द्वारा क्षेत्रों में त्यागे गए गोबर, मूत्र से मिट्टी में नाइट्रोजन का एक रूप पाया गया, जहां अमोनियम का स्तर 95 फीसदी तक तक कम था।

व्हाइट-लेपेड पेकेरी (टायसु पेकेरी) एक सूअर जैसा खुर वाला स्तनपायी है। ये जानवर 50 से 100 के समूह में जंगल में घूमते हैं, फलों को खाने वाले इन जानवरों या फ्रुजीवोर्स के द्वारा बड़ी मात्रा में गोबर, मूत्र को मिट्टी में त्याग दिया जाता हैं। इस तरह की प्रक्रिया से नाइट्रोजन के अलग-अलग रूप जारी होते हैं, जो पौधे के विकास में एक प्रमुख तत्व है। ये जानवर दुनिया भर में खासकर पूरे मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वन नाइट्रोजन चक्र में लगभग 70 फीसदी स्थलीय नाइट्रोजन निर्धारण और 50 फीसदी स्थलीय नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

साओ पाउलो रिसर्च फाउंडेशन-एफएपीईएसपी की अगुवाई में प्रकाशित अध्ययन से पता चला है कि इन फल खाने वाले जानवारों के द्वारा क्षेत्रों में त्यागे गए गोबर, मूत्र से मिट्टी में नाइट्रोजन का एक रूप पाया गया जहां अमोनियम का स्तर 95 फीसदी तक तक कम था। पहली बार इन जानवरों के नाइट्रोजन चक्र के महत्व के बारे में पता चला है। लेकिन अब उष्णकटिबंधीय जंगलों से बड़े स्तनधारी गायब हो रहे हैं। जिसके कारण पारिस्थितिक तंत्र का बड़ा नुकसान होने के आसार हैं। यह अध्ययन फंक्शनल इकोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। किसानों को पता है कि फसल की अधिक पैदावार हासिल करने के लिए नाइट्रोजन चक्र कितना महत्वपूर्ण है। जुगाली करने वालों जानवरों की उपस्थिति नाइट्रोजन चक्र पर उनके गोबर, मूत्र त्यागने से घास उपजाने में मदद मिलती है, जिसमें सूक्ष्मजीवों की गतिविधि भी शामिल है। शोधकर्ता नाचो विल्लर ने कहा हमारे नवीनतम अध्ययन से पता चलता है कि फल खाने वाले बड़े स्तनधारी उष्णकटिबंधीय जंगलों में एक ही सेवा प्रदान करते हैं। विलार ब्राजील के रियो क्लारो में साओ पाउलो स्टेट यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ बायोसाइंसेज से जुड़े एक शोधकर्ता हैं।

अध्ययन से यह भी पता चलता है कि ये जानवर नाइट्रोजन को पुनः विभाजित करते हैं, जो कि उन क्षेत्रों को उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं तथा पोषक तत्व बनाए रखते हैं ताकि पौधे का विकास होता रहे। शोधकर्ताओं के अनुमान के अनुसार, ऐसे क्षेत्र जहां फल खाने वाले जानवर नहीं रहते हैं उन क्षेत्रों की तुलना में चार गुना अधिक अमोनियम और 50 गुना अधिक नाइट्रेट होता हैं। शोधकर्ताओं ने दक्षिण अमेरिका के शाकाहारी जानवरों का उपयोग किया, जिसमें ब्राजील के सेरा डू मार स्टेट पार्क (साओ पाउलो स्टेट) का सबसे बड़ा अटलांटिक रैनफ़ॉरेस्ट रिजर्व जिसमें 15 वर्ग मीटर के 86 वन भूखंड शामिल थे। बड़े स्तनधारियों के प्रवेश को रोकने के लिए आधे भूखंडों को 2010 से बंद कर दिया गया है। सभी जानवर अन्य भूखंडों में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। फैंस और खुले भूखंडों पर लगे कैमरा ट्रैप ने अन्य फल खाने वाले जानवरों के बीच व्हाइट-लेप्ड पेकेरीज, कॉलरड पेकेरीज (पेकरी तजाकू) और टेपर्स की मौजूदगी या अनुपस्थिति पाई गई।

सूक्ष्मजीव, अमोनियम और नाइट्रेट

इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने गीले और सूखे मौसमों में एकत्र किए गए आठ जानवरों के जाने से रोकने वाले भूखंडों से मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण किया। अलग-अलग भूखंडों में जूसरा पाम भिन्न-भिन्न पाया गया है। खुले भूखंडों से मिट्टी में, अमोनियम का स्तर 95 फीसदी से अधिक था और नाइट्रिफिकेशन (अमोनियम से नाइट्रेट में रूपांतरण) भी मिट्टी में सूक्ष्मजीवों की संख्या अधिक थी। यद्यपि पौधे अमोनियम को अवशोषित करते हैं, उनका चयापचय तुरंत नाइट्रेट का उपयोग कर सकता है, इसलिए यह पौधे के विकास के मामले में अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है।

विलन ने कहा अटलांटिक रेनफॉरेस्ट में पेकेरी के कुल स्तनपायी जीवों के 80 फीसदी से 90 फीसदी तक रहते हैं। इन जानवरों के बड़े समूह बड़े इलाके में घूमते हैं, जंगल में खाद डालते हैं। तपीर जानवरों का घनत्व कम है, इसलिए नाइट्रोजन चक्र में उनका योगदान उतना अच्छा नहीं है, लेकिन प्रत्येक जानवर द्वारा ती है। त्यागे गए गोबर, मूत्र काफी है, साथ ही प्रत्येक जानवर बीजों को भी फैलाता है। इसी समूह द्वारा किए गए एक अन्य अध्ययन में पहले ही दिखाया गया था कि किस प्रकार पेकेरिज़ और टेपियर प्रजातियों की विविधता में अधिक योगदान करते हैं। यह विशाल फलों का क्षेत्र जानवरों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जानवरों के बड़ी मात्रा में गोबर, मूत्र त्यागने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। जानवरों, पौधों और मिट्टी के सूक्ष्मजीवों (मलमूत्रों से प्रेरित) के लिए चक्र, शोधकर्ताओं को ऐसे क्षेत्रों के विवरण के रूप में "फ्रूटिंग लॉन" शब्द का प्रस्ताव करने के लिए प्रेरित करता है।

अफ्रीकी सवाना और अन्य घास के मैदानों में प्रमुख खाद्य खपत और भोजन की उपलब्धता के बीच सकारात्मक प्रतिक्रिया है। समूह के अनुसंधान के अगले चरणों में यह जांच शामिल होगी कि क्या बड़े स्तनधारियों के साथ पौधों की परस्पर क्रिया के कारण नाइट्रोजन में वृद्धि उनके कार्बन अवशोषण को बढ़ाती है और मिट्टी से ग्रीनहाउस गैसों के निकलने को कम करती है। यदि ऐसा है, तो वैश्विक जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए पौधे-पशु की परस्पर क्रिया को एक प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए।

जलवायु परिवर्तन के चलते बच्चों के भोजन में घट रही है विविधता, बढ़ रहा है कुपोषण

बढ़ते तापमान के साथ बच्चों के आहार में विविधता में घट रही है जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान के चलते बच्चों के आहार में विविधता कम हो रही है साथ ही उसमें पोषक तत्वों की मात्रा भी घट रही है। जिसका सीधा असर पोषण पर पड़ रहा है। गौरतलब है कि पहले बच्चों में कुपोषण के लिए गरीबी, शिक्षा और स्वच्छता की कमी को वजह माना जाता था। पर इस नए शोध से पता चला है कि बच्चों में कुपोषण के लिए बढ़ता तापमान और जलवायु परिवर्तन भी उतना ही जिम्मेवार है। ऐसे में अनुमान है कि इन क्षेत्रों में हो रही प्रगति के बावजूद आने वाले वक्त में जलवायु परिवर्तन के चलते बच्चों के आहार विविधता में कहीं ज्यादा गिरावट आ जाएगी।

यह जानकारी हाल ही में जर्नल एनवायरनमेंट रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित शोध में सामने आई है। यह शोध 19 देशों के 107,000 बच्चों पर किया गया है, जो दुनिया के अलग-अलग महाद्वीपों से सम्बन्ध रखते हैं। इस शोध में शोधकर्ताओं ने आहार में मौजूद विविधता और जलवायु परिवर्तन के सम्बन्ध को समझने के लिए लम्बे समय के दौरान तापमान में हो रही वृद्धि, बारिश और बच्चों में कुपोषण के स्तर का अध्ययन किया है। उनके अनुसार जलवायु और आहार विविधता के बीच सीधा सम्बन्ध है। तापमान बढ़ने के साथ आहार विविधता में कमी देखी गई है, जबकि इसके विपरीत कुछ क्षेत्रों में जहां बारिश में वृद्धि हो रही है वहां आहार विविधता में भी वृद्धि देखी गई थी।

पौधों की सीओ2 को अवशोषित करने की क्षमता में गिरावट

एक अध्ययन के अनुसार उष्णकटिबंधीय और बोरियल वन अपनी सीओ2 अवशोषित करने की क्षमता का 45 प्रतिशत से अधिक गंवा सकते हैं।वन और भूमि पारिस्थितिक तंत्र आज मानवजनित सीओ2 प्रदूषण के 30 फीसदी को अवशोषित करते हैं। लेकिन तेजी से बढ़ता तापमान इन प्राकृतिक तरीके से अवशोषित करने वालों को कुछ दशकों के भीतर कार्बन 'स्रोतों' में बदल सकता है। शोधकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा यह जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई लड़ने में एक और चुनौती है। जलवायु वादी अक्सर सीओ2 को पौधों के भोजन के रूप में वर्णित करते हैं, यह सुझाव देते हैं कि भविष्य में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि होगी, पौधों की वृद्धि में भारी उतार-चढ़ाव होगा। लेकिन नए अध्ययन से पता चलता है कि तापमान एक निश्चित सीमा से अधिक है, जो कि क्षेत्र और पौधों की प्रजातियों के अनुसार अलग-अलग होता है। पौधों की सीओ2 को सोखने की क्षमता में गिरावट आ रही है।

बढ़ती जनसंख्या, घटते संसाधन, कैसे होगा जीवन यापन?

अंकुर सिंह

जनसंख्या वृद्धि कहीं न कहीं हमें आने वाले समय में भयंकर दुष्परिणाम की तरफ ले जा रही है, इसपर हम आज न सचेत हुए तो आने वाले समय में संसाधनों के लिए महायुद्ध जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता हैं । क्योंकि दैनिक उपयोग के संसाधन जैसे की पेट्रोल, डीजल, पेयजल, निवास और खेती हेतु भू-भाग इत्यादि सीमित मात्रा है।

जनसंख्या नियंत्रण कानून यदि तत्काल में प्रभावी नहीं किया गया तो आने वाले निकट भविष्य में संसाधनों के लिए देश में गृह-युद्ध का सामना करना पड़ेगा । जब सीमित संसाधन के लिए उपयोगकर्ता ज्यादा होंगे तो उन संसाधनों पर अधिकार के लिए भ्रष्टाचार और अपराध भी बढ़ेंगे। जैसा की हमारे देश में कृषि योग्य भूमि विश्व का 2.4% है , पेय-जल विश्व का 4% है और जनसंख्या विश्व का 20% हैं जो कहीं न कहीं ये इंगित करती है कि भविष्य में हालात रोटी एक और खाने वाले दस जैसे होने वाली हैं। जनसंख्या नियंत्रण पर हमें अपने पड़ोसी देश चीन से सबक लेनी चाहिए चीन 96 लाख वर्ग किलोमीटर में पसरा है और भारत 33 लाख वर्ग किलोमीटर से भी कम में है, इस तरह आंकड़ों के हिसाब से भारत की आबादी चीन से कम है, लेकिन क्षेत्रफल की तुलना से देखें तो यहां जनसंख्या घनत्व में हम पहले से ही चीन से आगे निकल चुके है। आज के समय में चीन में प्रति मिनट जन्म-दर 11 बच्चें का और हिंदुस्तान में 33 बच्चों का, इस आकड़ों के आधार पर हम कह सकते हैं की यदि जनसंख्या नियत्रंण के लिए जल्द को कठोर दंडात्मक कानून नहीं बनाया गया तो आने वाले 5-7 साल में चीन को पछाड़ नंबर एक पर काबिज होंगे, जो कि विकास में बाधक होगा क्योंकि संसाधन उतने ही रहेंगे और उपयोगकर्ताओं की संख्या ज्यादा होने से भुखमरी, बेरोजगारी, आपराधिक गतिविधि, और बीमारी जिसे संकट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सबके इलाज के लिए उतने अस्पताल ना होंगे, सृजित उतने रोजगार ना होंगे, खेतों में पैदावार अन्न से सबकी भूख ना मिटेगी और सबको अच्छी और सस्ती शिक्षा ना होने से अशिक्षितों के वजह से लोग तनाव ग्रस्त होकर आपराधिक प्रवृत्ति के तरफ रुख करेंगे और पर्यावरण ज्ञातों के अनुसार भू-भाग पर 33% पेड़ - पौधे भी

होना चाहिए संतुलित पर्यावरण के लिए।

भविष्य में संसाधन के संकट और आपराधिक गतिविधियों पर रोकथाम पर अंकुश रखना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में जन्मे बालकवि बैरागी जी के नारे हम दो हमारे दो पर अध्यादेश लाना होगा। जहाँ तक मेरा मानना है हम दो हमारे दो के जगह हम दो हमारे एक का कानून लाना चाहिए, इसके लिए पहले लड़के-लड़कियों में लिंग के आधार पर भेदभाव मिटाना होगा (हाँ मानता एक संतान में एक डर हैं असमय संतान की मृत्यु का, उस अवस्था में हम देश में संचालित विभिन्न अनाथालयों से किसी बच्चे को गोद लेकर उसे सुखद भविष्य भी दें सकते हैं)। आंध्रा, गुजरात महाराष्ट्र, ओडिशा और गुजरात जैसे कुछ राज्यों में परिवार नियोजन जैसे प्रावधान हैं, अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में दो संतानों तक वाले अभिभावक को चुनाव लड़ने की छूट रहेगी ऐसा मुद्दा भी चर्चा में हैं, बेशक क़ाबिले तारीफ भी है ऐसा कानून लेकिन ऐसे कानून केवल पंचायत स्तर पर ही नहीं अपितु राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा चुनाव और बाकी सरकारी सुविधाओं में भी समय-सीमा (कानून बनने के बाद जिनके ज्यादा संतानें होंगी उनको इन सब सुविधाओं से वंचित किया जाएँ, कानून के पूर्व जिनके संतानों की संख्या ज्यादा हो उन्हें सुविधाएँ पूर्व की भांति मिलती रहे) के साथ लागू होना चाहियें। जनसंख्या नियंत्रण कानून चीन ही नहीं बल्कि बहुत के देशों ने यही कानून बनायें , उदाहरण के रूप में ईरान को ही ले लिजिये 1990 में वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति ख़ुमैनी साहब ने हम दो हमारे दो का कानून लाएँ, जिसके आधार पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने करुणाकरण समिति का गठन किया, जिस समिति ने काफी अध्ययन के बाद ये स्वीकार किया भारत में भी ईरान जैसा जनसंख्या नियंत्रण कानून का जरुरत हैं कानून की जरुरत हैं, वो अलग बात हैं की किस राजनीतिक कारणवश वो कानून अभी तक नहीं बन पाया यदि नियम उस समय लागू हो गया होता तो आज हमारे देश की जनसंख्या सवा सौ करोड़ होती, साल 1975-76 में जनसंख्या नियंत्रण हेतु नसबंदी जैसे तानाशाही कानून तो आया जिसमें अविवाहित पुरुषों को भी पकड़कर नसबंदी किया गया था, जिससे लोगो के बीच एक गलत सन्देश गया। 22 फरवरी, 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने न्यायमूर्ति एम एन वेंकटचलैया (जिन्होंने राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन और मनरेगा जैसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में महत्वपूर्ण योगदान किया) की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर 4 जज, 2 सांसद और कई बड़ी हस्ती थे, इस आयोग ने दो साल के विस्तृत अध्ययन के बाद कहा कि संविधान में अनुच्छेद 47अ को जोड़िये और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाइये दुर्भाग्य से कुछ राजनीतिक समीकरणों के वजह से इस कार्य का भी शुभ आरम्भ नहीं हो पाया।

आज देश के विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून पर सभी राजनीतिक दलों को राष्ट्रहित में साथ आना होगा और सामाजिक संगठनों, धार्मिक गुरूओं, शिक्षित और युवा वर्गों को चाहिए की लोगों को जनसंख्या विस्फोट पर अंकुश के लिए जागरूक करें।

गर्भवती थी यूपी में मारी गयी डॉल्फिन

पोस्टमार्टम में मिला भ्रूण प्रशासन इस बात को छुपा रहा है कि युवकों द्वारा मारी गई डॉल्फिन गर्भवती थी

गौरव गुलमोहर

उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़-रायबरेली सीमा से गुजरने वाली शारदा सहायक नहर में स्तनधारी गंगा डॉल्फिन को धारदार हथियार और लाठी-डंडों से मारने का वीभत्स वीडियो ने देशभर के लोगों को परेशान कर दिया था। मामले का जब पड़ताल किया गया तो पाया कि घटना में मारी गई डॉल्फिन गर्भवती थी।

8 जनवरी को अपनी रिपोर्ट में क्षेत्रीय वन अधिकारी और नवाबगंज थाना प्रभारी दोनों से बात की थी, लेकिन दोनों अधिकारियों ने यह नहीं बताया था कि डॉल्फिन गर्भवती थी। ग्राम प्रधान मनोज कुमार सिंह ने बताया कि उनके पास एक फोटो है, उसमें डॉल्फिन और छोटे डॉल्फिन का शव नजर आ रहा है। फोटो 31 दिसम्बर को मारी गई डॉल्फिन के पोस्टमॉर्टम के समय का है। डॉल्फिन और उसके बच्चे के शव के साथ वाली फोटो पुलिस विभाग में भी कुछ लोगों के पास मौजूद है। मामले की सच्चाई जानने के लिए दुबारा क्षेत्रीय वन अधिकारी आर. के. सिंह से बात की तो वे कहते हैं कि "गांव वाले ऐसा बता रहे हैं कि दूसरी डॉल्फिन भी थी लेकिन उसका कोई सिग्नल ट्रेस नहीं हो रहा है। बाकी वहां पानी बहुत कम था, मौके पर दूसरी डॉल्फिन होने की गुंजाइश ही नहीं थी।

आर. के. सिंह से 31 दिसम्बर को मारी गई डॉल्फिन के गर्भवती होने की बात पूछी तो उन्होंने जानकारी नहीं होने की बात की। लेकिन पोस्टमार्टम स्थल पर तो आप रहे होंगे? इस सवाल के जवाब में वे कहते हैं कि "पोस्टमॉर्टम के समय जिला वन अधिकारी, कुछ एनजीओ और पशु डॉक्टर भी मौजूद थे। हम इतनी गहराई से उसके (डॉल्फिन) के पेट में नहीं झांक रहे थे। लेकिन डॉक्टर ने जो देखा होगा उसे लिखा होगा। हमें ज्यादा पता नहीं है।

अमित शाह ने किया कोयला मंत्रालय के सिंगलविंडो क्लीयरेंस पोर्टल का शुभारंभ

- **जनवरी 2021 में लांच होगा व्यावसायिक कोयला खनन की नीलामी का अगला चरणः प्रल्हाद जोशी**
- **भारत की सबसे पहली व्यावसायिक कोयला खनन**
- **नीलामी के विजेताओं के साथ कोयला मंत्रालय ने किए समझौते**

एजेंसियांः भारत में कोयला खदान शुरू करने के लिए जरूरी सभी क्लीयरेंसस और मंजूरियों को दिलाने में सहयोग देने के लिए कोयला मंत्रालय ने सोमवार को एक सिंगल विंडो क्लीयनरेंस पोर्टल लांच किया। केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी की उपस्थिति में भारत की सबसे पहली व्यावसायिक कोयला खनन नीलामी के विजेताओं के साथ समझौते करने के लिए नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में इस पोर्टल को लांच किया।

कार्यक्रम में जोशी ने व्यावसायिक कोयला खनन के लिए खदानों की नीलामी के अगले चरण के जनवरी 2021 में लांच किए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमने कोयला क्षेत्र में व्यापक सुधार किए हैं और अब कोयला क्षेत्र राष्ट्र में बड़े बदलावों का वाहक बनेगा। प्रल्हाद जोशी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साहसिक एवं निर्णायक नेतृत्व में कोयला क्षेत्र की व्यापक कायापलट हुई है। सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल सरकार के 'मिनीमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस' दृष्टिकोण को मजबूती देता है। यह पोर्टल कोयला क्षेत्र में 'ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। देश में कोयला खदान शुरू करने के लिए अभी 19 बड़े अप्रूवल या क्लीयरेंसस (मंजूरी) लेने पड़ते हैं। इनमें माइनिंग प्लान एंड माइन क्लोजर प्लान, माइनिंग लीज लेना, पर्यावरण एवं वन, वन्य जीव, सुरक्षा, परियोजना प्रभावित परिवारों का विस्थापन, कर्मचारी कल्याण जैसे क्षेत्रों से जुड़ी मंजूरियां शामिल हैं। ये सभी मंजूरियां केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा दी जाती हैं। ये सभी मंजूरियां प्राप्त करने के किसी सम्मिलित प्लेटफॉर्म की अनुपस्थिति में खनन परियोजना प्रस्तावकों को विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों और सरकारी विभागों के समक्ष अलग-अलग आवेदन करने पड़ते हैं, जिससे कोयला खदानों से कोयला उत्पादन शुरू करने में देर होती है। लेकिन अब इस प्रक्रिया को जल्द पूरा करने में यह सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल मदद करेगा। इस पोर्टल का माइनिंग मॉड्यूल सोमवार को लांच किया गया, जबकि अन्य मंजूरियों से जुड़े मॉड्यूल चरणबद्ध तरीके से शुरू किए जाएंगे।

कार्यक्रम में कोयला मंत्रालय ने भारत की सबसे पहली व्यावसायिक कोयला खनन नीलामी के सफल विजेताओं- वेदांता लिमिटेड, अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड, जिंदल पावर लिमिटेड, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड सहित कुल 19 विजेताओं के साथ समझौते भी किए। इस नीलामी की सफलता से भारत का लगभग 20 प्रतिशत कोयला आयात कम होगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त होगा। एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, जोकि कोयला मंत्रालय का एकमात्र 'लेन-देन सलाहकार' है, ने इस नीलामी प्रक्रिया को विकसित करने और आयोजित करने में सहयोग दिया है। प्रल्लहाद जोशी ने सभी राज्यों से इन सभी खदानों को जल्द से जल्द शुरू करने में अपना सहयोग देने की अपील की, ताकि भारत अपने विशाल कोयला भंडार का समुचित उपयोग कर कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके।

गौरतलब है कि व्यावसायिक कोयला खनन के लिए सफलता पूर्वक नीलाम की गईं 19 खदानों से राज्यों को 6,656 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। नीलामी प्रक्रिया के दौरान आवेदकों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा के चलते 66.75 प्रतिशत का अधिकतम और 27 प्रतिशत का औसत प्रीमियम प्राप्त हुआ। ये खदानें 05 राज्यों- मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड एवं महाराष्ट्र में फैली हैं और इनसे सम्मिलित रूप से 51 मिलियन टन का सालाना अधिकतम अनुमानित कोयला उत्पादन होगा।

प्रल्हाद जोशी ने कहा कि खनिज संपदा से संपन्न विभिन्न राज्यों के अनुभव और विभिन्न हितग्राहियों से मिली फीडबैक के आधार पर सरकार खनन क्षेत्र में भी बड़े ढांचागत सुधार लाएगी। ये सुधार बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा करेंगे और खनिज उत्पादन बढ़ाकर देश में आत्म-निर्भरता को बढ़ावा देंगे। मुझे विश्वास है कि खनन क्षेत्र में होने वाले इन सुधारों से भारत को अपनी वास्तविक क्षमता के साथ खनिज उत्पादन करने में मदद मिलेगी इन सुधारों के तहत खनन क्षेत्र में उद्योग जगत के अनुकूल 'ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देने वाले कई कदम उठाए जाएंगे।

महिला सशक्तिकरण के लिए सामुदायिक विज्ञान को बढ़ावा देने की जरूरत

रांची संवाददामा : बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ ओंकार नाथ सिंह ने मंगलवार को बायोकण्ट्रोल यूनिट एवं गृह विज्ञान विभाग के भवन को देखा तथा समस्यायों की जानकारी ली. प्रभारी डॉ विनय कुमार ने बताया की बायोकण्ट्रोल यूनिट की दो हजार प्रतिदिन ट्रायोकार्ड उत्पादन की क्षमता है. जो धान एवं मक्का फसल में समेकित नाशीजीव प्रबंधन में काफी लाभदायक है. कुछ वर्षो तक कृषि विभाग द्वारा क्रय कर इसे किसानों के बीच वितरित किया गया. इस तकनीक को किसानों के हित में सरकार के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार की जरूरत है. कुलपति ने कहा कि आधुनिक कृषि में समेकित नाशीजीव प्रबंधन में ट्रायोकार्ड की उपयोगिता को देखते हुए बायोकण्ट्रोल यूनिट को सशक्त करने के हर संभव प्रयास किये जायेंगे.

गृह विज्ञान विभाग के भ्रमण के दौरान विभागाध्यक्ष डॉ रेखा सिन्हा ने बताया कि यह ईकाई आधुनिक उपकरणों से लैस है. यहाँ युजीसी मान्यताप्राप्त वोकेशनल डिग्री कोर्स में तीन बैच के छात्र अध्ययनरत है. ईकाई द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन पर छमाही सर्टिफिकेट कोर्स एवं ट्रेनिंग तथा गृह वाटिका पर ट्रेनिंग का आयोजन किया जाता है. मडुआ एवं सोयाबीन तथा सब्जी एवं फलों के मूल्यवर्धन से अनेकों उत्पाद बनाये जाते. इन कार्यक्रमों से प्रदेश की हजारों महिलाएँ लाभान्वित हुई है. प्रदेश की बहुतायत महिलाएँ कृषि कार्यो से जुडी हुई है. प्रदेश की ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं सशक्तिकरण के लिए विश्वविद्यालय में गृह विज्ञान विभाग का उन्नयन कर सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय खोले जाने की जरूरत है.

कुलपति ने तकनीकी मानवबल की व्यवस्था करने का भरोसा दिया. प्रदेश में सामुदायिक विज्ञान तकनीकी के क्षेत्र को बढ़ावा देने सबंधी प्रयास करने तथा प्रस्ताव देने की बात कही. कुलपति ने कहा कि बायोकण्ट्रोल यूनिट, गृह विज्ञान विभाग और मशरूम उत्पादन यूनिट के भवनों की स्थिति दयनीय है. आधुनिक कृषि से जुड़े इन तीनों अवयवों के यूनिट को सुदृढ़ करने पर जोर दिया जायेगा. मौके पर वैज्ञानिकी सलाहकार डॉ पीके सिंह ने तीनों अवयवों के तकनीकी पहलुओं से कुलपति को अवगत कराया।

रेलवे सुरक्षा बल ने जागरूकता अभियान चलाया

रांचीः 3 जनवरी को, रेलवे सुरक्षा बल ने सुबह 08:00 बजे चतरा पंचायत, थाना टाटीसिल्वे स्थित पुराना चतरा बस्ती के वार्ड नंबर 07 और 08 में मुखिया श्री सोहन मुंडा के साथ ग्रामीणों को ट्रेन पर पत्थर ना मारने के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया गया। जिसमें ग्रामीणों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया साथ ही साथ ग्रामीणों को रेलवे सुरक्षा बल द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 182 एवं महिला सुरक्षा से संबंधित मेरी सहेली अभियान पर विशेष चर्चा की गई तथा ग्रामीणों को इससे अवगत कराया गया। ग्रामीणों ने रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाए जा रहे इन अभियानों की सराहना की और यह भरोसा दिया कि भविष्य में ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटना की पुनरावृति नहीं होगी।

रेलवे सुरक्षा बल ने अफीम बरामद किया

रांची संवाददाता : 14जनवरी को रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट, रांची के अधिकारी एवं जवान, स्पेशल टास्क फोर्स टीम एवं नन्हे फरिश्ते टीम ने रांची स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 01 पर दो व्यक्तियों को संदिग्ध अवस्था में देखा, उसके बाद उन दोनों व्यक्तियों को रोका गया और पूछताछ के दौरान एक व्यक्ति भाग गया, लेकिन दूसरे व्यक्ति से पूछताछ के दौरान एवं जांच करने पर उसके पास से चार प्लास्टिक बैग में अफीम पाया गया और उसने बताया कि वह उसने सिविल कोर्ट के नजदीक अली नामक व्यक्ति से 1,20,000 में खरीदा है, तथा उस व्यक्ति ने यह भी बताया कि वह यह अफीम पंजाब ले जाकर बेचेगा और पैसे कमाएगा । आरपीएफ निरीक्षक श्रीमती सुनीता पन्ना ने उक्त व्यक्ति के कब्जे से अफीम को मौजूद गवाहों के समक्ष जप्त किया जिसका वजन 3.4 ' आंका गया, जिसकी कुल कीमत लगभग 350000 आँकी गई। अग्रिम कार्यवाही हेतु राजकीय रेल थाना रांची को सुपुर्द किया गया, जहां एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियुक्त विशाल कुमार उम्र 28 वर्ष के विरुद्ध केस दर्ज किया गया।

कोरोना का राज्यवार ब्यौरा

एजेंसियां

पश्चिम बंगाल में 7 हजार से ज्यादा मामले हैं केरल में सबसे ज्यादा 69,209 मामले सक्रिय हैं जबकि इसके बाद महाराष्ट्र में 53,852 और उत्तरप्रदेश में 8,881 मामले सक्रिय हैं

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में 19,90,759 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से 18,86,469 ठीक हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर कर्नाटक है जहाँ अब तक 931,997 मामले सामने आ चुके हैं।

तीसरे नंबर पर आंध्रप्रदेश है, जहां अब तक 885,985 मामले सामने आ चुके हैं। केरल 847,848, तमिलनाडु में 830,772, दिल्ली में 632,429, उत्तरप्रदेश में 596,528, पश्चिम बंगाल में 565,272, ओडिशा में 333,310, राजस्थान में 315,181ण

छत्तीसगढ़ में 293,501, तेलंगाना में 291,872, हरियाणा में अब तक 266,309, बिहार में 257,610 जबकि गुजरात में भी अब तक संक्रमण के करीब 255,872 मामले सामने आ चुके हैं। जबकि उनमें से 245,107 मरीज ठीक हो चुके हैं।

महिलाओं द्वारा संचालित जोहार एग्री मार्ट

पेज एक का शेष .....

कृषि सामग्री खरीदने के लिए दूर बाजार नहीं जाना पड़ता है, वहीं सामग्री की गुणवत्ता को लेकर भी अब चिंता नहीं रहती है। जोहार एग्री मार्ट में उत्तम खाद, बीज, कृषि यंत्र सुविधा, मौसम की जानकारी, बाज़ार सुविधा, मिट्टी जांच, मछली/पशु चारा आदि सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। एग्री मार्ट के जरिए खाद-बीज के अलावा अन्य कृषि सामाग्री की भी बिक्री की जा रही है, जैसे- डी.ए.पी, यूरिया, कुदाल, फावड़ा, कीटनाशक, पशु आहार इत्यादि।

जोहार एग्री मार्ट से सीख रहे हैं किसान उन्नत खेती के गुर

जोहार एग्री मार्ट में खेती से जुड़े सामानों की बिक्री के अलावा किसानों को उन्नत खेती एवं तकनीक से भी जोड़ने का कार्य किया जाता है। एग्री मार्ट के जरिए तकनीक का इस्तेमाल कर किसानों को उन्नत खेती संबंधित सलाह एवं उपाय भी बताए जाते है। उत्पादक कंपनी से जुड़े किसानों को एग्री मार्ट अंतर्गत व्हाट्सएप के जरिए तकनीकी सलाहकारों से जोड़ा गया है। ये सलाहकार सुबह 10.30 से शाम 5 बजे तक रोजाना किसानों को खेती से जुड़ी जानकारी एवं आ रही दिक्कतों का हल बताते है। हर एग्री मार्ट ने कृषक मित्रों एवं किसानों को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जोड़ रखा है, जिससे किसान बस एक व्हाट्सएप मैसेज (फसल/पशु की फोटो) भेजकर ही उससे संबंधित सहायता/सहयोग व्हाट्सएप पर ही प्राप्त कर रहे हैं।

उत्पादक कंपनी से उद्यमिता की ओर अग्रसर महिला किसान

गिरिडीह स्थित गिरधन महिला उत्पादक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सदस्य नीलिमा बताती हैं कि लगभग 160 से ज्यादा

उत्पादक समूह से जुड़ी महिला किसान एवं अन्य किसान नियमित रूप से एग्री मार्ट से ही कृषि सामग्री एवं सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। गिरिडिह जिले में संचालित जोहार एग्री मार्ट ने गुणवत्ता एवं कृषि सेवाओं की वजह से अब अपनी एक अलग पहचान बनाई है।

राज्यभर का आंकड़ा देखा जाए, तो कुल 11 एग्री मार्ट के जरिए करीब 4 हजार से ज्यादा किसानों को सेवाएं उपलब्ध करा कर 73.40 लाख से अधिक का कारोबार किया गया है।

पर्यटन के इकोसिस्टम की ब्रांडिंग के लिए तैयार हो रहा है प्रदेश

मुरलीधर

इको टूरिज्म और धार्मिक टूरिज्म सर्किट के लिये होगा विकास

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की पहल पर इको टूरिज्म फेस्टिवल के तहत इको रिट्रीट के आयोजन की योजना बन चुकी है। इसके लिए नेतरहाट, मसानजोर, डिमना लेक, पतरातू डैम जैसे जगहों का चयन किया गया है। इको रिट्रीट का मुख्य उद्देश्य झारखण्ड में पर्यटन के इकोसिस्टम की ब्रांडिंग करना है। इसके तहत इको रिट्रीट के पहले चरण में नेतरहाट में इको टूरिज्म शुरू करने की योजना है। साथ ही, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार नयी पर्यटन नीति जल्द राज्य की जनता के समक्ष पेश करेगी।

इको रिट्रीट देगा अद्भुत आनन्द

इको टूरिज्म फेस्टिवल में विभिन्न तरह के कार्यक्रम का आयोजन होगा। पर्यटक इको रिट्रीट के जरिये झारखण्ड के सुन्दर पर्यटन स्थलों का आनंद लेंगे। इस क्रम में एडवेंचर स्पोर्ट्स, नेचुरल ट्रेल, साइकिलिंग, ऑफ रोड ड्राइविंग, लेक एडवेंचर स्पोर्ट्स, रोप क्लाइम्बिंग सहित पारंपरिक नृत्य/गीत आयोजित करने की योजना है। इको टूरिज्म सर्किट के तहत लातेहार- नेतरहाट- बेतला-चांडिल-दलमा-मिरचैया फॉल और गेतलसुद डैम को विकसित करने की योजना है। धार्मिक टूरिज्म सर्किट के मध्यम से कौलेश्श्वरी-इटखोरी-रजरप्पा-पारसनाथ के विकास पर कार्य होगा।

फूलों की घाटी पर्यटकों का मोहेगा मन

झारखण्ड आने वाले पर्यटकों को नेतरहाट के मैग्नोलिया पॉइंट और मसानजोर में फूलों की घाटी देखने का मौका जल्द प्राप्त होगा। इसके लिए फूलों

की घाटी के निर्माण की योजना प्रस्तावित है। धुर्वा में ट्राइबल थीम पार्क, दुमका और रांची में ग्रामीण पर्यटन केंद्र, सरायकेला-खरसावां, साहिबगंज और दुमका में हस्तकरघा पर्यटन केंद्र, राजमहल-साहिबगंज-पुनाई चौक गंगा सर्किट का निर्माण कर राजमहल- भागिया-उधवा फॉसिल पार्क को जोडने की योजना, दुमका के बासुकीनाथ में वेसाइड एमेनिटीज, मसानजोर में अतिरिक्त टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स निर्माण, शिवगादी, साहिबगंज और मसानजोर में एडवेंचर टूरिज्म समेत अन्य योजनाएं प्रस्तावित हैं।

ग्रामीण संस्कृति से होंगे रूबरू

झारखण्ड की ग्रामीण संस्कृति से रूबरू कराने के लिये रूरल टूरिज्म को सरकार विकसित करेगी। चिन्हित गांव को पर्यटन से जोड़ने के लिये गांव को नया स्वरुप दिया जायेगा। नेतरहाट के आदिवासी बहुल सिरसी गांव में निर्मित मिट्टी के घरों को सांस्कृतिक टूरिज्म के तहत मॉडल गांव के रूप में विकसित करने की योजना है। सिरसी ग्राम से होमस्टे स्कीम की शुरुवात भी की जानी है, ताकि बाहर के पर्यटक हमारे राज्य की संस्कृति को नजदीक से देख एवं यहां के स्वादिस्ट व्यंजन का स्वाद ले सकें। इसके अतिरिक्त धार्मिक टूरिज्म, सांस्कृतिक टूरिज्म, शिल्प और व्यंजन टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, वीकेंड गेटवे, फिल्म टूरिज्म, मनोरंजक पार्क, कल्याण पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य हो रहा है।

इस तरह वर्तमान सरकार झारखण्ड के पर्यटन को विश्वपटल पर लाने की ओर अग्रसर है। जहां सुन्दर झरनों से लेकर हिल स्टेशन तक, आध्यत्मिक स्थलों से लेकर जलाशयों तक, घने जंगलों से लेकर वन्यजीव अभ्यारण्य तक पर्यटकों के स्वागत को आतुर हैं।

फोटो न्यूज

कंबल से मिली ठिठुरती लोगों को राहत

रांची : श्री सेवा संस्थान लालपुर रांची स्थित संस्थान के तत्वाधान में दिनांक 17/01/2021 रविवार को कंबल वितरण कार्यक्रम रखा गया !इस कार्यक्रम के तहत यतू रोड स्थित दुर्गा मंदिर ,पहाड़ी मंदिर ,हनुमान मंदिर, मेन रोड स्थित हनुमान मंदिर, फिरयालाल चौक ,शहीद चौक ,सर्जना चौक होते हुए रांची रेलवे स्टेशन के प्रांगण में गरीब और जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया !इस दौरान लगभग 200 कंबल क्षेत्रों में वितरित किया गया ! इस कार्यक्रम में श्री सेवा संस्थान के अध्यक्ष वेणु गोपाल पाठक, सचिव प्रमोद कुमार, कोषाध्यक्ष काजल कुमारी के साथ मानव राय, घुनचुन राय ,सूरज कुमार जी बी शास्त्री आदि अन्य कई लोग मौजूद थे।

पेड़ जरूर लगायें, हर जीव को आश्रय मिलता है

अफ्रिका से फैले रोग से देश में दुधारू पशुओं पर आफत

इसका देश पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा, जहां अधिकांश डेयरी किसान या तो भूमिहीन हैं या सीमांत भूमिधारक हैं और उनके लिए दूध सबसे सस्ते प्रोटीन स्रोत में से एक है

भारत में दुधारू पशुओं में यह त्वचा रोग तेजी से फैल रहा है। साल की शुरुआत से ही केरल के वायनाड जिले के काम्मना गांव में एक अजीब लेकिन परिचित भय व्याप्त है। यह भय कुछ-कुछ कोविड-19 जैसा ही है। इस बार वायरस भी अलग है और होस्ट भी। कम्मना के रहने वाले साजी जोसेफ कहते हैं, " मुझे नहीं पता कि मेरी पांच में से तीन जर्सी गायों को ये बीमारी कब और कैसे हुई। जनवरी के पहले सप्ताह में अचानक तेज बुखार के साथ उनके शरीर पर गांठें दिखाई देने लगीं। एक सप्ताह के भीतर, वे कमजोर हो गए। कम दूध उत्पादन से मुझे रोजाना 700 रुपये का नुकसान हो रहा है। गांव के अन्य 200 डेयरी किसान भी इसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। यहां तक कि संक्रमित बैल और भैंस भी गाड़ियां खींचने या कृषि कार्य करने में असमर्थ हैं।

स्थानीय पशु चिकित्सकों ने इसे गांठदार त्वचा रोग (एलएसडी) के रूप में पहचाना है। यह एक वायरल बीमारी है, जो मवेशियों में लंबे समय तक अस्वस्थता का कारण बनती है। यह पूरे शरीर में दो से पांच सेंटीमीटर व्यास के नोड्यूल (गांठ) के रूप में पनपता है। खास कर, सिर, गर्दन, लिंब्स और जननांगों के आसपास। गांठ धीरे-धीरे बड़े और गहरे घाव बन जाते है। एलएसडी वायरस मच्छरों और मक्खियों जैसे खून चूसने वाले कीड़ों द्वारा आसानी से फैलता है। यह लार, दूषित पानी और भोजन के माध्यम से भी फैलता है। पशु चिकित्सकों का कहना है कि इस बीमारी का अभी कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। भारत में यह पहली बार देखा जा रहा है।

अफ्रीका से आया भारत में

ऐतिहासिक रूप से, एलएसडी अफ्रीका तक ही सीमित रहा है, जहां यह पहली बार 1929 में खोजा गया था। लेकिन हाल के वर्षों में यह अन्य देशों में फैला है। 2015 में तुर्की और ग्रीस जबकि 2016 में इसने बाल्कन, कॉकेशियान देशों और रूस में तबाही मचाई। जुलाई 2019 में बांग्लादेश पहुंचने के बाद से, यह एशियाई देशों में फैल रहा है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन (एफएओ) के एक जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, यह बीमारी 2020 के अंत तक सात एशियाई देशों, चीन, भारत, नेपाल, ताइवान, भूटान, वियतनाम और हांगकांग में फैल चुकी है। इसके अलावा, दक्षिण- पूर्व एशिया के कम से कम 23 से ज्यादा देशों में एलएसडी का बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है।

भारत में दुनिया के सबसे अधिक, 303 मिलियन मवेशी हैं. यहां यह बीमारी सिर्फ 16 महीनों के भीतर 15 राज्यों में फैल चुकी है. अगस्त 2019 में, ओडिशा से एलएसडी का पहला संक्रमण रिपोर्ट हुआ था। अध्ययन से पता चलता है कि देश में वायरस पहले से ही म्यूटेट हो सकता है। जबलपुर में वेटरनरी साइंस एनिमल हसबेंड्री कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर वंदना गुप्ता ने पाया है कि वायरस का यह स्वरूप ओडिशा में पाए गए पहले वायरस के स्वरूप से अलग है। वह चेतावनी देती है, ''हमें तत्काल रोकथाम की रणनीति अपनाने की आवश्यकता है। यह बीमारी अन्य देशों में कैसे व्यवहार करती है, इसकी तुलना में यहां अलग तरीके से व्यवहार कर सकती है। चूंकि एलएसडी वायरस शीप और गोट पॉक्स से संबंधित है, हमें यह समझने की जरूरत है कि क्या यह भेड़ और बकरियों में भी फैल सकता है।

नए नियम से मेडिकल कॉलेजों में कम हों जाएंगे वैज्ञानिक शिक्षक

एजेंसियां

एनएमसी के नए नियम के चलते कई शिक्षक वैज्ञानिक जो मेडिकल कॉलेज में अध्यापन का काम कर रहे हैं प्रभावित होंगे। इस निर्णय को शिक्षक दल ने चुनौती दी है। मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा विज्ञान से पढ़ाई करके एमएससी या पीएचडी की डिग्री हासिल करके वैज्ञानिक शिक्षक के तौर पर अध्यापन करने वालों पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के नए नियम से गाज गिरने वाली है। दरअसल ऐसे वैज्ञानिक शिक्षकों के फीसदी को मेडिकल कॉलेजों में कम करने का निर्णय लिया गया है। मेडिकल कॉलेज संकायों में इनकी संख्या 30 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी तक करने की गाइडलाइन राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के जरिए ली गई है।

वर्तमान में देशभर में मेडिकल कॉलेजों में चार हजार से अधिक "गैर-चिकित्सा" शिक्षक कार्यरत हैं, जिनमें से कई नए आरएमसी दिशानिर्देशों से प्रभावित होंगे। इस बीच राष्ट्रीय एमएससी मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन (एनएमएमटीए) ने इन नियमों को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है, जो 17 फरवरी, 2021 को अगली सुनवाई करेगी। दरअसल मेडिकल एमएससी का पुराना कोर्स कंपलीट करने के बाद जो वैज्ञानिक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए भी अवसर हैं लेकिन अब इन पर नई गाइडलाइन नकेल कस रही है। जबकि मेडिकल एमएससी या पीएचडी करने के बाद नेट की परीक्षा में भी ऐसा कोई विषय नहीं मिलता है। एनएमएमटीए ने इस मामले को ने शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने भी उठाया है।

जहरीले प्रदूषक और संक्रमण के मेल से वन्यजीव की आबादी में आई गिरावट: शोध

एजेंसियां

शोधकर्ताओं ने बताया कि वन्यजीवों के दूषित आवासों के जहरीले पदार्थों और संक्रमण के मेल ने बहुत अधिक संख्या में जानवरों को प्रभावित किया, जिससे वन्यजीव आबादी में गिरावट आई

एंथ्रोपोजेनिक बदलाव जैसे कि शहरीकरण, खेती में कीटनाशकों का उपयोग, औद्योगीकरण आदि मानवीय गतिविधियों में जहरीले प्रदूषकों का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। इनका वन्यजीवों पर किस तरह प्रभाव पड़ रहा है इसी को लेकर जॉर्जिया विश्वविद्यालय ने एक अध्ययन किया है। अध्ययन में कहा गया है कि वन्यजीवों के प्रदूषकों के संपर्क में आने से संक्रामक रोगों का फैलना प्रभावित हो सकता हैं।

ओडियम स्कूल ऑफ इकोलॉजी में पोस्ट-डॉक्टोरल सहयोगी सेसिलिया सेंचेज के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने यह पता लगाने के लिए एक गणितीय मॉडल बनाया है। इस मॉडल की मदद से इस बात का पता लगाया गया है कि कैसे विषाक्त पदार्थ वन्यजीव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और उन प्रभावों से वन्यजीव आबादी और मनुष्यों में बीमारी फैलने का खतरा कैसे बढ़ जाता है। ओडुम स्कूल और कॉलेज ऑफ वेटरनरी मेडिसिन के रिचर्ड हॉल ने कहा कि संक्रामक घटकों या दूषित पदार्थों के एक साथ संपर्क में आने से वन्यजीव आबादी पर प्रभाव बढ़ सकते हैं। जब हम हाल कि परिदृश्यों को देखते है तो वन्यजीव वास्तव में इनसे फैलने वाले रोगों को बढ़ा सकते हैं। रोग फैलाने वाले वन्यजीवों से यह घरेलू जानवरों और लोगों में फैल सकते हैं। दुनिया भर में शहरी, औद्योगिक और कृषि विकास जैसी मानवीय गतिविधियां तेजी से बदल रही हैं। इन गतिविधियों में जहरीले प्रदूषकों का उपयोग बढ़ गया है, जिसमें भारी धातु और कीटनाशक शामिल हैं। मानव द्वारा किए जा रहे बदलाव अक्सर वन्यजीवों को आकर्षित करते हैं जैसे खेतों में काम करते समय पक्षीयों के द्वारा खाना ढूढना, असुरक्षित उर्वरकों का उपयोग जो खेतों से सीधे खाद्य स्रोतों में पहुंच जाते हैं।

डॉ. सहदेव राम ने केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के भुगतान के लिये प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

रांची : केंद्रीय कर्मचारी एवं अधिकारी परिसंघ के अध्यक्ष डॉ. सहदेव राम ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते तथा पेंशनधारियों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त के भुगतान के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा है। डॉ. सहदेव राम ने कहा है कि देश की आर्थिक स्थिति में व्यापक सुधार देखी गयी है, रिकार्ड राजस्व की वसूली हुयी है और राष्ट्रीय राजकोष में पर्याप्त राशि जमा हुआ है। केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत कि किस्त के मद में 1300 करोड़ बनता है। वर्तमान में सुधरी हुई अर्थव्यवस्था के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते तथा केंद्रीय पेंशनधारियों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जो जनवरी 2020 से देय है उसे देने पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाये।

डॉ. सहदेव राम ने पत्र में कहा है कि प्रधानमंत्री राहत कोष में 3500 करोड़ अतिरिक्त रकम है जो 65 सालों से उपयोग में नहीं लाया गया है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों तथा पेंशनधारियों ने जो कि इस देश के वरिष्ठ नागरिक हैं उन्हें राहत प्रदान की जाये।

तीन दशक के शोध के बाद भारत में उगेगा रंगीन कपास

एजेंसियां

सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य तौर पर गहरा भूरा और भूरा से खाकी, सफेद और हरे रंग के कपास का इस्तेमाल किया जाता था

भारत रंगीन कपास की व्यावसायिक खेती के लिए इसके बीजों की प्रजाति जारी करने से कुछ ही महीने दूर है। शोधकर्ता 16301डीबी और डीडीसीसी1 का फार्म ट्रायल कर रहे हैं। इन प्रजातियों से भूरे रंग के कपास का उत्पादन होगा।

आने वाले दिनों में सफेद कपास की बजाय रंगीन कपास उगा करेंगी।इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च (आईसीएआर) के कपास पर ऑल इंडिया को-ऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट (एआईसीआरपी-कॉटन), कोयम्बटूर का नेतृत्व कर रहे एएच प्रकाश कहते हैं, "इस साल 21 अप्रैल को आ-ईसीएआर की कमेटी की वार्षिक बैठक होगी, जिसमें इस कपास की व्यवहार्यता का मूल्यांकन किया जाएगा और इसके बाद इसकी प्रजातियों को व्यावसायिक खेती के लिए जारी किया जाएगा।" दूसरे संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर ये एजेंसी सुनिश्चित कर रही है कि इस कपास के उत्पादन में निरंतरता बनी रहे।

कपास की 16301डीबी प्रजाति को आईसीएआर की सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च (सीआईसीआर), नागपुर ने विकसित किया है। दुनियाभर में सबसे ज्यादा उगाये जा रहे गोसोपियम हरसटम की पांच रंगीन कपास की प्रजातियों के मूल्यांकन के बाद इस कपास की प्रजाति विकसित की गई है।वहीं, ड-ीडीसीसी-1 प्रजाति को एग्रीकल्चरल साइंस यूनिवर्सिटी, धारवाड़ (कर्नाटक) ने विकसित किया है। भारत और अन्य उपोष्णकटिबंधीय देशों में पाई जानेवाली जी अरबोरियम प्रजाति के 6 रंगीन कपास के मूल्यांकन के बाद ये प्रजाति विकसित की गई है। प्रकाश ने कहा कि 15 अन्य रंगीन कपास की प्रजातियों को लेकर परीक्षण चल रहा है और इनके परिणाम अलग-अलग चरणों में हैं।

विकासशील देशों को प्रतिवर्ष 5 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता,तभी रह पायेंगे जलवायु परिवर्तन के साथ

एजेंसियां

यदि जलवायु में बदलाव इसी तरह जारी रहता है तो यह जरुरत 2030 तक बढ़कर 21,94,875 करोड़ रुपए और 2050 तक 36,58,125 करोड़ रुपए पर पहुंच जाएगी।

जलवायु परिवर्तन के अनुकूल रहने के लिए विकासशील देशों को हर साल 512,138 करोड़ रुपए की जरुरत है। यदि जलवायु में बदलाव इसी तरह जारी रहता है तो यह जरुरत 2030 तक बढ़कर 21,94,875 करोड़ रुपए (30,000 करोड़ डॉलर) और 2050 तक 36,58,125 करोड़ रुपए (50,000 करोड़ डॉलर) पर पहुंच जाएगी। यह जानकारी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी यूनेप अडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट 2020 में सामने आई है। 2020 जो न केवल कोरोना महामारी का वर्ष था, यह वर्ष जलवायु परिवर्तन के भी नाम रहा। हाल ही में नासा ने 2020 को भी दुनिया के सबसे गर्म वर्ष के रूप में मान्यता दी है, जो 2016 के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर पहुंच गया है। जिस तरह से इस वर्ष, बाढ़, सूखा, तूफान और टिड्डियों के हमले जैसी घटनाएं सामने आई हैं वो स्पष्ट तौर पर जलवायु परिवर्तन का ही नतीजा हैं। इससे भी चिंता की बात यह है कि सदी के अंत तक वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि 3.2 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाएगी। ऐसे में क्या है इसका समाधान। आज पैरिस समझौते पर अमल करने की जरुरत है जिससे ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को सीमित किया जा सके, जिससे तापमान में हो रही वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोका जा सके।

क्यों जरुरी है जलवायु अनुकूलन?

जिस तरह से जलवायु में बदलाव आ रहे हैं उसके चलते बाढ़, सूखा, तूफान जैसी आपदाओं का आना सामान्य सी बात बन गया है। यदि प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान को देखें तो 2020 में इनके चलते 15,36,412 करोड़ रुपए (21,000 करोड़ डॉलर) का नुकसान हुआ था, जबकि 2019 में यह नुकसान करीब 12,14,498 करोड़ रुपए का था। समय के साथ इन आपदाओं से होने वाला नुकसान भी बढ़ता जा रहा है।

हालांकि इस नुकसान की भरपाई तो की जा सकती है पर इसके चलते जितने लोगों की जिंदगियां गई, जितने घर उजड़े उसकी भरपाई करना नामुमकिन है। इन

आपदाओं का काफी बोझ भारत, चीन जैसे विकासशील देशों को उठाना पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन इससे होने वाले नुकसान से बचने का एक बेहतरीन उपाय है। दुनिया के ज्यादातर देश इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 72 फीसदी देशों ने जलवायु अनुकूलन को लेकर योजनाएं भी बनाई हैं, लेकिन धन का आभाव और उनपर काम ने करने के कारण यह अधर में अटकी हैं। विकासशील देशों के सामने वित्त एक बड़ी समस्या है। जिसके आभाव में यह देश अभी भी इन आपदाओं से निपटने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जलवायु सम्बन्धी खतरों को कम करने में अनुकूलन का बहुत बड़ा हाथ है। 2019 में ग्लोबल कमीशन ऑन अडॉप्टेशन का अनुमान था कि अनुकूलन पर खर्च किए 131,69,250 करोड़ रुपए (180,000 करोड़ डॉलर) के निवेश से करीब 519,45,375 करोड़ रुपए (710,000 करोड़ डॉलर) का लाभ पहुंचेगा।

ऐसे में जलवायु अनुकूलन के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों तरीकों से वित्त पोषण जरुरी है, जिसके लिए तत्काल प्रयास किए जाने चाहिए। प्रकृति आधारित और कम लागत वाले समाधानों पर भी जोर देना चाहिए। साथ ही स्थानीय समस्याओं पर भी ध्यान देना जरुरी है। इसमें जलवायु परिवर्तन, जैवविविधता के संरक्षण, पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा और उनका निरंतर प्रबंधन अहम है। साथ ही वहां रहने वाले लोगों का कल्याण और विकास भी जरुरी है।

E ZONE CARE

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

• **Repair your laptop with 3-month warranty.**

info@ezonecare.in, ezonecare.in
Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, Ranchi 93108 96575, 70047 69511
Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm
SUNDAY CLOSED

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मनोरंजन सिंह द्वारा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित एवं सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2,रातू रोड, रांची- 834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : **JHAHIN/2019/78094**, email:greenrevolt2019@gmail.com.☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।